immediately measures and steps should be taken to save the Mills from closure.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I associate myself with him.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, I associate myself with him.

SHRI M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): Sir, I also associate myself with him.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, it may be noted that the final hearing on this matter is on 30-3-2001.

MR. CHAIRMAN: NO. Nothing more.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: If no Government attorney appears before the BIFR and no assurance is given that the Mills will be revived, all the five mills in Kerala will be closed.

MR. CHAIRMAN: That is all right.

Conversion of Jaunpur-Aurihar Rail-Line into Broadgauge

श्री श्यामलाल (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, पूर्वांचल के जनपद जौनपुर के रेल जंक्शन (ब्रॉड गेज) से जनपद गाजीपुर के जंक्शन औरिहार (ब्रॉड गेज) को मिलाने वाले 62 किलोमीटर लंबे मीटर गेज रेल मार्ग को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के संबंध में मैं आपके माध्यम से इस विशेष उल्लेख द्वारा भारत सरकार के रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, यह ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित जनपद जौनपुर एवं गाजीपुर अति घने आबाद होने के साथ-साथ पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। महोदय, घनी आबादी के कारण इन जनपदों के लोग जीविकोपार्जन हेतु देश के बड़े-बड़े औद्योगिक एवं व्यावसायिक शहरों में आया-जाया करते हैं। पूर्वांचल के दो जनपदों गाजीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे के औरिहार जंक्शन) से उत्तर रेलवे के जौनपुर जंक्शन को मिलाने वाला 62 किलोमीटर का रेल पथ मीटर गेज में है जब कि दोनों उल्लिखित जंक्शनों के ब्रॉड गेज के रेल पथ भारत के सभी भागों से जुड़े हुए हैं। पहले औरिहार से जौनपुर तक मीटर गेज की ट्रेन 10-12 डिब्बों में तीन बार आवागमन करती थी, परन्तु 8-10 वर्षों से मात्र एक डिब्बे की रेल बस दिन में मात्र एक बार आवागमन करती है। इन दोनों जनपदों के मध्य राजकीय परिवहन निगम की बसों की सेवा भी उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग पर क्रमशः सैदपुर बाजार, औरिहार बाजार, पतरही बाजार, चन्दवक, केराकत, नई बाजार, देवकली, मुफतीगंज, धर्मापुर आदि बाजारें अवस्थित हैं तथा कई महाविद्यालय आदि हैं। इस रेल पथ के मीटर गेज व एक डिब्बे की रेल बस के कारण जनमानस के आवागमन की भारी समस्या है। लोग इस एक डिब्बे के भीतर व बाहर तथा छतों पर भीड़युक्त एवं खतरे से भरी यात्रा के लिए बाध्य हैं। सारा औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास अवरुद्ध है।

मान्यवर, जब राष्ट्र विकास की तरफ उन्मुख है, जनमानस के सार्वभौमिक विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आवागमन के नए-नए संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसी दशा में मीटर गेज रेल पथ को ब्रॉड गेज रेल पथ में परिवर्तित किए जाने की सामयिक व बहुआयामी मांग को अविलम्ब पूर्ण करने का अनुरोध किया जाता है तथा ब्रॉड गेज में परिवर्तन की प्रक्रिया-काल में कम से कम 8-10 डिब्बे की ट्रेन पूर्ववत् समयबद्ध तरीके से तीन बार चलाए जाने की मांग की जाती है।

Generation and allocation of power to Rajasthan

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, in terms of the Indus-Water Treaty and consequent agreement on sharing of the waters of Sutlej, Ravi and Beas rivers, Rajasthan has lodged claims for share in power generation in Thein, Anandpur Sahib, Mukerian, U.B.D.C. Stage-II and Shahpur Kandi Hydro Electric Projects. The Government of India may refer the claims of Rajasthan for share of power in the above five projects to the Supreme Court for its opinion. The Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, may be requested to fix the price and the transportation charges at a reasonable level, by notifying a special price for the use of natural gas resources in Rajasthan. I impress upon the Ministry of Petroleum and Natural Gas to allocate additional gas for the Ramgarh Extension Project. Also, the Government may give techno-economic clearance for the installation of additional units at Ramgarh. The Government of India should impress upon the Government of Himachal Pradesh for Rajasthan's share, as per the agreement dated 30.06.1984, in the Kol Dam Hydel Project. In case the project is handed over to NHPC, then the Government of India should consider allocating Rajasthan's share as per the agreement, to maintain the sanctity of Inter-State agreements. Further, in order to settle long- standing Inter-State disputes on sharing of power from hydro-electric projects, it is proposed that an Inter-State Tribunal be constituted consisting of eminent engineers, headed by a judge of a High Court or the Supreme Court. I urge upon the Govemment to take effective steps for generation and allocation of power to the State of Rajasthan.

Need to abolish child labour

MISS MABEL REBELLO (Madhya Pradesh): Sir, there is an urgent need for the elimination of child labour and enactment of a separate legislation to form a commission on child labour at the Government of India as well as at State levels.

As per the reports of the Government of India, the total number of